



Adhunik Samachar

आधुनिक समाचार

आधुनिक भारत का आधुनिक नजरिया

प्रयागराज से प्रकाशित एवं सम्पूर्ण भारत वर्ष मे प्रसारित



१० वर्ष चिह्नित करें



आई.टी.आई में सीधे प्रवेश NAINI INDUSTRIAL TRAINING CENTRE

(Govt. Affiliated, Star Graded, Record Holder, ISO Certified Training Centre)

नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रवेश कार्यालय का हुआ उद्घाटन



नैनी। नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रवेश कार्यालय का हुआ उद्घाटन भारत सरकार द्वारा मान्यता पास नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र प्रवेश कार्यालय का सिविल डिफेंस प्रयागराज के मंडल अधिकारी रौनक गुसा के द्वारा किया गया प्रशिक्षण केंद्र के प्रवेश प्रभारी मोहम्मद कौसर ने बताया कि प्रयागराज में न्यूनतम शुल्क मुद्दों प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यहां इंडस्ट्रियल विजिट सेमिनार, ग्रुप डिस्क्यूशन, आदि कराया जाता है जिसे प्रशिक्षणार्थीयों का सर्वानिंदिन विकास होता है। केंद्र गुणवत्ता परिषद द्वारा स्टार गेंडिंग प्राप्त है। केंद्र के कंप्यूटर शिक्षक रोहित शुक्ल ने बताया कि सरकार द्वारा छात्रवृत्ति एवं टैबलेट की सुविधा उपलब्ध है प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण के दौरान सरकार द्वारा मार्ड भी दिया जाता है प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण के दौरान सरकार द्वारा मार्ड भी दिया जाता है। मुख्य अतिथि ने नवीन प्रवेशार्थीयों का स्वागत एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है प्रयागराज नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण के द्वारा रौनक गुसा इस अवसर पर निरीक्षक विजय पांडे, रोहित शुक्ला, सदिन श्रीवास्तव, मोहम्मद कौसर, प्रदीप जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे।

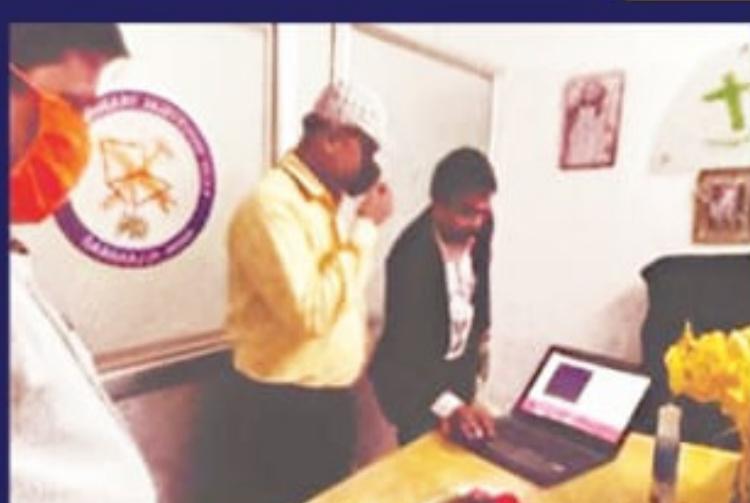


नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के छात्र रेलवे में चयनित



नैनी। नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के चार छात्रों का सिक्कदराबाद में रेलवे में चयनित होने पर संस्थान परिवार ने बधाई दी है। प्रयागराज कराया तहसील के नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के चार छात्रों का रेलवे के धारा रेल प्रोजेक्ट सिक्कदराबाद में चयन होने से विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा छात्र का सम्मान एवं अभिनन्दन किया। इस अवसर पर संस्थान के प्रवेश प्रभारी मोहम्मद कौसर ने इन छात्रों का समारोहपूर्वक अभिनन्दन एवं सम्मान करते हुये कहा कि यह विद्यालय के लिये गौरव की बात है संस्थान के शिक्षक सदैव इस बात पर बल देते हैं कि छात्र अच्छा रीखें और अपने भविष्य को उज्ज्वल एवं सफल बनावें। उन्होंने भविष्य में और मेहनत व लगन से अध्यापन व अध्ययन करने हेतु शिक्षकों और छात्रों का आङ्गन किया। इस अवसर पर केक काटकर केंद्र का स्थापना दिवस भी मनाया गया।

Admission Open 2024-25



श्री सत्यदेव दुबे (प्रधानाचार्य)
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भदोही



श्री सुजीत श्रीवास्तव (प्रधानाचार्य)
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नैनी, प्रयागराज



इ. अर्चना सरोज (द्रेनिंग एवं पलेसमेन्ट, अधिकारी
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खागा, फतेहपुर

- ★ C.O.P.A.
- ★ Fitter
- ★ Computer Teacher Training
- ★ Electrician
- ★ Fire Safety & Industrial Security
- ★ Repair of Refrigerator & A.C.
- ★ Welding Technology
- ★ Certificate in YOGA
- ★ Security Service
- ★ Computer Hardware & Maintenance

Naini ITC Honored by U.P. State Industrial Association

JEEVAN EXPRESS NEWS

PRAYAGRAJ: A seminar was organized by Uttar Pradesh State Industrial Association on Friday. In which Naini Industrial Training Center was honored with a citation by the association's president Arvind Rai for providing high quality skilled workers. Mohammad Kausar received the honor from the Centre. On this occasion, all the entrepreneurs of Prayagraj including Arinnd Rai Sheetal Plastics, Anat Chandra Ventura Private Limited, BLKHN Engineering Works, S Shukla, Overseas Food Agro Private Limited, union officials and all the industrialists were present.



Visit us at www.nainiiti.com Call: 9415608710, 7459860480



सम्पादकीय

जल संकटः सियासत से
नहीं बुझेगी दिल्ली की
प्यास, टैंकर माफिया के
सामने बेबस है सरकार

सियासत अपनी जगह है, पर टैकर माफिया पर अंकुश लगाने में असमर्थ दिल्ली सरकार पानी के ट्रीटमेंट व स्टोरेज पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रही। वैसे तो मौसम की मार झेल रहे दिल्लीवासियों को हर साल भीषण गर्मी के दौरान पानी की भारी कमी से जूझना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्लीवासी पानी की भारी किलुत का सामना कर रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी दिल्ली के जल संकट के लिए कभी दिल्ली के उपराज्यपाल को, तो कभी हरियाणा सरकार को दोषी ठहराती रहीं, तो वहीं उपराज्यपाल जल संकट के लिए पानी की चोरी और बर्बादी को मुख्य कारण बता रहे हैं। सर्वीच्य न्यायालय ने टैकर माफिया पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और यह भी माना है कि इसी बजह से यह समस्या इतना विकराल रूप ले पाई है। अब जब हिमाचल साफ कह चुका है कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए 136 क्यूसेक पानी नहीं है, शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए दिल्ली को पानी देने का फैसला अपर रिवर यमुना बोर्ड पर छोड़ा है कि उसके पास जल बंटवारे के जटिल मुद्दे के समाधान की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। सवाल यह भी है कि जब हरियाणा द्वारा दिल्ली को पूरा पानी दिया जा रहा है, तो दिल्ली पानी की किलुत क्यों झेल रही है। दिल्ली वाले पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं, मारामारी करने पर क्यों उतारू है? असलियत में यह सिलसिला दिल्ली में आप की सरकार के अस्तित्व में आने के साथ से ही लगातार जारी है। दिल्ली को हरियाणा से कुल 1,050 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए। एक से 22 मई तक हरियाणा मुनक नहर के कैरियर लाइन नहर यानी सीएलसी में 719 क्यूसेक और दिल्ली सब ब्रांच यानी डीएसबी नहर में 350 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। मतदान के दो से तीन दिन पहले इसे 91 क्यूसेक तक कम कर दिया गया। जहां तक मुनक नहर की मरम्मत और रख-रखाव का सवाल है, इसका ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ना नितांत गलत है, क्योंकि नहर की मरम्मत और उसके रख-रखाव का जिम्मा हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग का है। हकीकत में मुनक नहर से पानी बगाना लाया जाता है। बगाना से पहले योद पानी का चोरी होती है, तो इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। यह तो रही दूसरे राज्यों से पानी आने, न आने की बात। कम पानी आने से वजीराबाद जलाशय का स्तर सामान्य से पांच फीट नीचे आ जाना खतरे का सकेत है। दिल्ली में जगह-जगह लोगों के लिए लगाए गए वाटर एटीएम की बात करें, जिसके बारे में भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के बढ़-चढ़कर दावे किए जा रहे थे, तो हकीकत यह है कि वे खराब पड़े हैं। जहां तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात है, तो हाल फिलहाल नौ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। दिसंबर तक द्वारका में एक नया प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन, असली समस्या तो पानी की मांग और उपलब्धता की है। दिल्ली में पानी की मांग 1,296 एमजीडी से 1,300 एमजीडी तक है, जबकि स्पूर्झ केवल 998.8 से 1,000 एमजीडी ही है। स्वाभाविक है 300 एमजीडी पानी की कमी तो बरकरार रहती ही है। जल संकट के मध्येनजर कुल 587 ट्र्यूबवेल लगाने की योजना थी। पहले चरण में इनमें से कुछ लोग भी, जिनसे 19 एमजीडी पानी मिल रहा है, जबकि दसरे चरण में 2,590 ट्र्यूबवेल के लिए 1,800 करोड़ की राशि की दरकार थी, जिसकी अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। फिर दिल्ली सरकार के जल बोर्ड की क्षमता केवल 90 करोड़ गैलन पानी के ट्रीटमेंट की ही है। हकीकत यह है कि दिल्ली सरकार खुद ही पानी के ट्रीटमेंट और स्टोरेज पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों की पानी की जरूरत कैसे पूरी कर पाएगी, यह समझ से परे है। जबकि सर्वीच्य न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए योजना पेश करने का निर्देश दिया है। ऐसे में जब तकरीबन 40-50 साल पुरानी पाइप लाइन लीकेज और जगह-जगह फटने से हजारों गैलन पानी की बर्बादी रोजर्मर्गरा की बात है, तो इनमें सुधार किए बिना आने वाले दिनों में दिल्ली वाले पानी के संकट से कैसे निजात पाएंगे, यह समझ से परे है। हिमाचल की मनाही और शीर्ष अदालत के अपर रिवर यमुना बोर्ड के पास जाने के लिए कहने के बाद देखेने वाली बात है कि अब दिल्ली सरकार पानी के लिए क्या कदम उठाएगी।

इंगमर बगमैन बन गया स्क्रीनप्ले राइटर

करीब 60 फिल्में लिखीं, 170 नाटक लेखे तथा 100 किताबें लिखीं। करीब 90 मिनट की उनकी फिल्मों की थीम बहुत अनोखी होती थी वे उनसे प्रभावित थीं। जब समय आया उहोंने इंग्लैण्ड को बुलाया और करारनामे के तहत कुछ समय के लिए उहें अपने विभाग में रख



निर्देशकों की प्रेरणा रहे। विश्व गणितज्ञ निर्देशक इंगमर बर्गमैन संयोग से स्क्रीनप्लैट राइटर बन गए। 14 जुलाई 1918 को स्वीडन में जन्मे बर्गमैन नाटक लिख रहे थे और उन नाटकों का सफल प्रदर्शन हो रहा था। एक नाटक 'कैस्पर' से 'डेथ' का निर्देशन करने का अवसर उन्हें मिला। नाटक के कई शो हुए और वह सफल रहा। स्टीना बर्गमैन उपन्यासकार-नाटककार यल्मर (प्रिंटेर्ट) बर्गमैन की विधता थीं, वे व्यक्तेन्स्क फिल्म इंडस्ट्री स्टूडियो के स्क्रिप्ट विभाग की प्रमुख थीं। साथ ही अमेरिकन फिल्म ड्रामा तकनीक लेखक के भयंकर स्क्रीनप्लैट को सुधारना था। जब वे नए संस्करण के साथ गए, तो उनके काम को अच्छा माना गया। पर उस स्क्रीनप्लैट पर कभी फिल्म नहीं बनी। लेकिन इगमैन को मासिक वेतन पर स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी पर रख लिया गया। उन्हें विभाग में डेस्क, टेलीफोन और अपना ऑफिस मिल गया। ये बातें इंगमर बर्गमैन ने अपनी किताब 'इमेजेसः मार्ट लाइफ इन फिल्म' में लिखी हैं। उनका काम था सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक अपने टेबल पर बैठ कर उपन्यासों, कहानियों अथवा आई हर्ड सिनेमाइस से स्क्रीनप्लैट तैयार

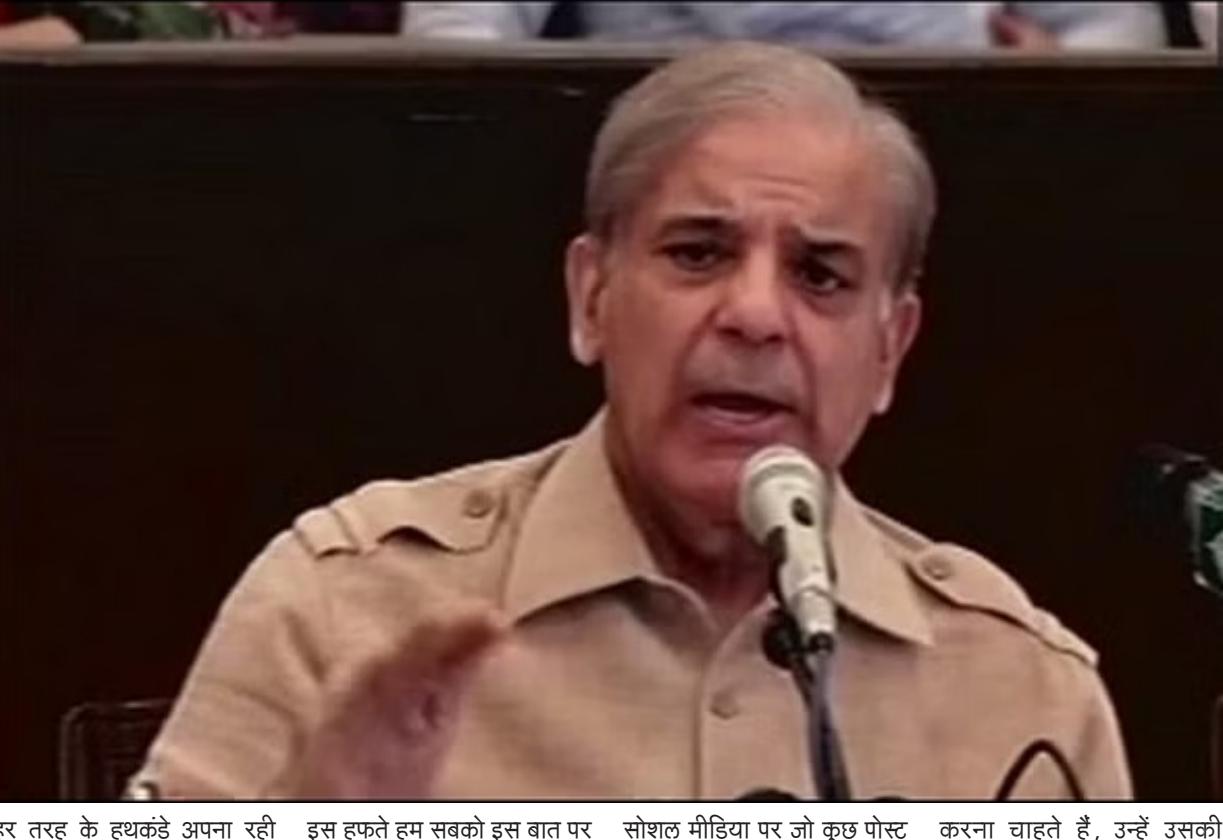
अपने ही बनाए नियमों को सुबह शाम तोड़ रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके मंत्री

इसे पाकिस्तान का विडब्ल्यू हो कहे कि जहां आप लोगों को एक्स का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है, वहीं प्रधानमंत्री खुद और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सुबह-शाम एक्स का उपयोग कर अपने ही नियम को तोड़ रहे हैं। असैन्य थे। आज भी मेरे एक बुजुंग सहकर्मी नासिर जैदी जीवित हैं, जो बताते हैं कि कैसे तानाशाह ने उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने की हिम्मत करने के लिए कोड़ों से पीटा था। आज असैन्य तानाशाही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए

पहुच सकते हैं। लिंकन विडबना
यह है कि जहां आप लोगों को एकस
का इस्तेमाल करने पर पांचदी लगा
दी गई है, वही प्रधानमंत्री खुद और
उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य
सुबह-शाम एकस का उपयोग कर
अपने ही नियम को तोड़ रहे हैं।

टोक, एक्स, फसबुक और
ग्राम जैसे सोशल मीडिया
रॉर्म पर गलत सूचनाओं से
टना है, जिससे 'फर्जी खबर'
ने वालों के खिलाफ मानहानि
मुकदमा दायर किया जा सके।
बात से हर कोई सहमत है कि

दिलाते हैं कि हमारे सीवधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसे आम नागरिक अभी तक पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं। यहां चिंता यह नहीं है कि नागरिकों को जो कुछ भी वे कहना या उपभोग पोस्ट की जाने वाली या देखा जाने वाली हर चीज पर जासूसी करने की अनुमति देगा। यह इंटरनेट फायरवॉल ग्रेट फायरवॉल की तरह है, जिसका उपयोग चीनी अधिकारी अपने नागरिकों पर नजर रखने के लिए करते हैं। यह इंटरनेट



है। यही नहीं, अब पत्रकारों के गायब होने और उनकी हत्या का खतरनाक चलन भी दिख रहा है। इससे पहले दुनिया भर के तानाशाहों की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ महीने पहले पूरे पाकिस्तान में एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब लोगों को वीपीएन इंस्टाल करना पड़ता था, जो सिस्टम को अनब्रॉक करने में मदद करता है, ताकि उपयोगकर्ता ट्रॉट कर सकें। इनमें से कुछ वीपीएन मुफ्त हैं, जबकि कुछ अन्य के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, तभी एक्स तक

हंसी आई कि एक्स को ब्रॉक किए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री को आप चुनाव में जीत की बधाई ट्वीट करके दी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके जवाब दिया। इस पाखंड को सबने समझ लिया कि पाकिस्तान के राजनेता कैसे अपने ही कानून उल्लंघन कर रहे हैं। अब पंजाब प्रांत की सरकार ने पंजाब मानहानि विधेयक, 2024 के लिए आधिकारिक रूप से गज़त अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे विवादास्पद कहा जाता है। नए कानून का उद्देश्य यूट्यूब,

किया जाता है, उनमें से कुछ नफरत से भरा और अस्वीकार्य होता है। लेकिन उन अकाउंट को बंद करने के बजाय, जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करत है, आप पूरे नेटवर्क को बंद नहीं कर सकते। पत्रकार समुदाय ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया है। गैर-लोकतात्त्विक बताते हुए इसकी निर्दा की है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से भी प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के कारण कड़ी आपत्ति जताई गई है। अंग्रेजी दैनिक द डॉन ने संपादकीय में लिखा है- 'ये घटनाक्रम इस बात की याद

अनुमति दी जानी चाहिए, आखिरकार नागरिक होने के नाते वे भी देश के कानून से बंधे हैं। बल्कि डर यह है कि इन हथकड़ों का इस्तेमाल पुलिस और सत्ता से असहमत केवल चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा।' इस हफ्ते की दूसरी चौकाने वाली खबर यह है कि शहबाज शरीफ सरकार अब इंटरनेट फायरवॉल बना रही है, जिसे कथित तौर पर अधिकारियों ने गुप्त रूप से लाग करना शुरू कर दिया है, जो उन्हें पाकिस्तानी उपयोगकर्ताओं द्वारा इंटरनेट पर

जानलेवा तम्बाकू का एक उपयोगी पहलू भी

उद्योग मंत्रालय का अधान कावररत गुण्टूर स्थित राष्ट्रीय तम्बाकू बोर्ड के अनुसार तम्बाकू भारत में उआई जाने वाली महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4.57 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

महामारा पर नियन्त्रण करने के लिये भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकु नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) शुरू किया गया था जिस पर हर साल एक बड़ी रकम खर्च होती। इसी कार्यक्रम के तहत

भारत का प्रमुख स्थान रहा। 2021 के दौरान, भारत उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश (एफआरस्टेट डेटा, 2021) और दुनिया में अनिर्मित तम्बाकू का चैथा सबसे बड़ा निर्यातक (आईटीसी ट्रेडमार्क डेटा 2021) रहा। भारत

जनुसार तम्हायापूर्व दुनिया में आयक
रूप से सबसे महत्वपूर्ण कृषि फसलों
में से एक है। यह सूखा सहने वाली,
कठोर और कम अवधि वाली फसल
है जिसे ऐसी मिट्टी पर उगाया जा
सकता है जहाँ अन्य फसलों की
खेती लाभप्रद रूप से नहीं की जा

वामन-प्रकार के गरे फुट्यू पयाइ वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन किया जाता है। देश के लगभग 15 राज्यों में तम्बाकू की खेती की जाती है, जो कृषि समुदाय की अर्थव्यवस्था और समृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। भारत में प्रमुख तम्बाकू उत्पादक राज्यों में गुजरात, गोवा, पर्सिया, उड़ीसा, कर्नाटक



की विदेशी मुद्रा अर्जित कराता है। तम्बाकू सेवन को मौत का पिछला दरवाजा माना जाता है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अभिलेखों के अनुसार देश में तम्बाकू जनित बीमारियों से प्रतिदिन औसतन 3500 लोगों की मौतें होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार 35 से अधिक उम्र के लोगों के तम्बाकू जनित बीमारियों के इलाज पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 1.77 लाख करोड़ रुपये खर्च हुये थे। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में 12 लाख से अधिक लोगों की मौत तम्बाकू जनित बीमारियों के कारण हर्याँ थीं जिनमें 2.40

गया है। लेकिन इस बेहद डारावने सच के पीछे एक सच और भी है जो कि अक्सर चर्चा में नहीं आ पाता है। यह दूसरा सच तम्बाकू उत्पादन और अर्थ व्यवस्था में इसके योगदान का है। भारत सरकार के गणित्य और उदयोग मंत्रालय के अधीन कार्यरत गुण्डूर स्थित राष्ट्रीय तम्बाकू बोर्ड के अनुसार तम्बाकू भारत में उआई जाने वाली महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4.57 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तम्बाकू बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय खजाने में 9,739.06 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कराता है। तम्बाकू बार्ड के रिकार्ड के

करता है, जो उनकी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं में भिन्न होती है। बोर्ड के अनुसार भारत ने 2020 में 766,000 टन से अधिक पत्ती का उत्पादन किया। यह वैश्विक उत्पादन का 9 प्रतिशत है। भारत में प्रमुख तम्बाकू उत्पादक राज्यों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और बिहार शामिल हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश देश के कुल उत्पादन में क्रमशः लगभग 45, 20 और 15 प्रतिशत का योगदान करते हैं। आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण कृषि फसलों में से एक वणिज्य मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान क्षेत्र का 0.27 प्रतिशत) क्षेत्र में उगाई जाती है, जिससे 75 करोड़ किलोग्राम तम्बाकू पत्ती का उत्पादन होता है। चीन और ब्राजील के बाद भारत क्रमशः दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और नियांतक है। फूंक्योर्ड वर्जीनिया(एफसीवी) तम्बाकू का उत्पादन 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र से लगभग 30 करोड़ किलोग्राम है, जबकि 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र से 45 करोड़ किलोग्राम गैर तम्बाकू का उत्पादन होता है। वैश्विक परिदृश्य में, भारतीय तम्बाकू का क्षेत्रफल 10 प्रतिशत और कुल उत्पादन का 9 प्रतिशत है। भारत में तम्बाकू उत्पादन की अन्ठी विशेषता यह है कि परे देश में फैली

और समाज के कमजोर वर्ग हैं। तम्बाकू से प्रतिवर्ष 4,400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जो देश के कुल कृषि-निर्यात का 4 प्रतिशत है, तथा 14,000 करोड़ रुपये उत्पाद शुल्क राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं, जो सभी स्रोतों से प्राप्त कुल उत्पाद शुल्क राजस्व का 10 प्रतिशत से आधिक है। भारत विश्व का प्रमुख तम्बाकू निर्यातक भारतीय तम्बाकू को 'पैसे के लिए मूल्य' माना जाता है। भारत तम्बाकू के प्रमुख निर्यातकों में से एक है, तथा ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। विश्व तम्बाकू व्यापार में देश की हिस्सेदारी मात्रा के हिसाब से 6 प्रतिशत तथा मूल्य के हिसाब कुछ बीड़ी कंपनियां भी हैं जिनमें लाखों महिला पुरुष काम करते हैं। बीड़ी बनाने का काम समूहे भारत में फैला हुआ है और इसमें महिलाओं एवं बच्चियां बहुतायत से जुड़ी हैं। लाखों की संख्या में ग्रामीण और शहरी गरीब महिला कामगार अपना परिवर्ग इससे पालती हैं। तेंदू पत्तों में तंबाकू फैलाकर और फिर शंकवाकार में मोड़ कर बीड़ी तैयार की जाती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक सर्व के अनुसार तम्बाकू सेवन के विविध स्वरूपों में बीड़ी पीने वाले वर्यस्कों का अनुपात 2009-2010 के दौरान 50.1 प्रतिशत था जो 2016-2017 के दौरान बढ़कर 57.0 प्रतिशत

